

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15012025-260261  
SG-DL-E-15012025-260261

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 337

No. 20]

DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSAH 23, 1946

[N. C. T. D. No. 337]

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2025

फा. सं. जी.जी.एस.आई.पी.यू./कॉर्ड/ओआरडी 37/83 बीओएम/2024/440.— गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 (1)(xi) के प्रावधानों के अनुपालन में गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने दिनांक 25/06/2024 को आयोजित अपनी 83वीं बैठक में कार्यसूची मद सं. 83•32 के द्वारा, 'दर्शन निष्णात उपाधि (मास्टर ऑफ फिलोसफी (एम०फिल०) डिग्री प्रदान किये जाने के लिये शासी कार्यक्रम शीर्ष से नये अध्यादेश -37 को अनमोदित किया है जिसे निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :

अध्यादेश 37: “दर्शन निष्णात उपाधि (मास्टर ऑफ फिलोसफी (एम. फिल) डिग्री प्रदान किये जाने के लिये शासी कार्यक्रम ”।

अनुप्रयोज्यता: यह अध्यादेश “नैदानिक मनोविज्ञान एवं मनशिविकित्सा समाज कार्य में दर्शन निष्णात” उपाधि प्रदान करने के लिए समस्त शासी कार्यक्रमों (शैक्षिक सत्र 2024–25 से अनुप्रयोज्य) पर

लागू होगा। यह अध्यादेश, प्रबंध मण्डल द्वारा दी गयी स्वीकृति की तिथि से ही प्रभावी हो जायेगा।

#### **1•0 परिभाषाएँ**

- 1•1 “अधिनियम” से अभिप्राय होगा समय—समय पर यथा संशोधित गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998।
- 1•2 “विश्वविद्यालय” से अभिप्राय होगा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।
- 1•3 “अध्ययन स्कूल” से अभिप्राय होगा स्कूल (स्कूल्स) अथवा विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस) जो कि अध्यादेश 2 के खण्ड 100 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये होंगे।
- 1•4 “केन्द्र” से मन्तव्य होगा, अध्यादेश 35 के खंड 1 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ‘उत्कृष्टता—केन्द्र’।
- 1•5 “महाविद्यालय/संस्थान” से अभिप्राय होगा एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकारों के द्वारा अनुरक्षित अथवा स्वीकृत किया गया हो और जो अधिनियम की धारा 2(i) में परिभाषितानुसार किसी संबद्ध महाविद्यालय/ संस्थान को सम्मिलित करता हो तथा इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार दर्शन निष्णात कार्यक्रम के लिये स्वीकृत हो।
- 1•6 “पाठ्य समिति (बीओएस)” का वही अभिप्राय होगा जैसा कि संबंधित विद्याध्ययन के विश्वविद्यालयी स्कूलों के अध्यादेश 2 खण्ड 2 के अंतर्गत पाठ्य समिति के बोर्ड को परिभाषित किया गया होगा। इसके साथ—साथ ‘पाठ्य समिति’ शब्दावली का उपयोग केन्द्र(३) की संचालन समिति पर भी लागू होगा। संचालन समिति की भूमिका, अध्यादेश 35 में परिभाषित इसकी भूमिका के अतिरिक्त, पाठ्य समिति की भूमिका के समान ही होगी। इसके अतिरिक्त, संचालन समिति का गठन भी अध्यादेश 35 में परिभाषितानुसार ही होगा। जहाँ कहीं भी ‘पाठ्य समिति’ शब्द का उल्लेख इस अध्यादेश में किया गया है, भविष्य में, अध्यादेश 35 के अन्तर्गत गठित केन्द्रों के संदर्भ में इसे संचालन समिति के रूप में ही पढ़ा/जाना जायेगा।
- 1•7 “अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ” (आर डी सी) का अभिप्राय होगा विश्वविद्यालय का अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ।
- 1•8 “पाठ्यक्रम कार्य” से अभिप्राय होगा, दर्शन निष्णात उपाधि (एम. फिल डिग्री) के लिये पंजीकृत छात्र द्वारा अपनाये जाने के लिये स्कूल/विभाग/ केन्द्र द्वारा, निर्धारित अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम।
- 1•9 “परीक्षा नियंत्रक (सी ओ ई)” से अभिप्राय होगा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक।
- 1•10 “विद्या विशेष” का अभिप्राय होगा वे ‘विषय विशेष’ जिनमें, दर्शन निष्णात उपाधि प्रमाण पत्र में उद्धृतानुसार दर्शन निष्णात की उपाधि प्रदान की जानी है। स्कूल शोध समिति (एस आर सी) संस्तुति करेगा और संबंधित स्कूल की पाठ्य समिति उस ‘विषय—विशेष’ की स्वीकृति देगी जिसमें स्कूल के माध्यम से दर्शन निष्णात की उपाधि प्रदान की जायेगी। संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता (डीन), स्कूल में जो दर्शन निष्णात उपाधि प्रदान करने के लिये पाठ्य समिति की स्वीकृति के पश्चात् विषय विशेष प्रस्तावित किये जाने हैं, अधिसूचना हेतु शोध एवं विकास अनुभाग को सूचित करेंगे।
- 1•11 “शैक्षिक सत्र” एक वर्षीय अवधि का होगा जो छः—छः मास के दो सत्रों में प्रभाजित होगा। शैक्षिक सत्र सामान्यतः प्रतिवर्ष के अगस्त मास के प्रथम कार्य दिवस से प्रारम्भ होगा। दर्शन निष्णात कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कार्य वाले भाग के संचालन के लिये विस्तृत शैक्षिक कलेन्डर को शोध एवं विकास अनुभाग अधिसूचित करेगा जबकि दर्शन निष्णात की समीक्षा के लिये शैक्षिक कलेन्डर को संबंधित कलेन्डर को संबंधित स्कूल शोध समिति (एस आर सी) अधिसूचित करेगी।
- 1•12 “शोध छात्र” से अभिप्राय होगा एक ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत दर्शन निष्णात के लिए पंजीकृत है और इसे छात्र कह कर भी उल्लिखित किया जायेगा।

- 1•13 "विदेशी शोध छात्र"** से अभिप्राय होगा भारतीय मूल के ऐसे विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत दर्शन निष्णात के लिये शोध छात्र के रूप में पंजीकृत हैं।
- 1•14 "विदेशी शिक्षण संस्थान"** से अभिप्राय होगा (i) एक ऐसा संस्थान् जो अपने गृह देश में विधिवत् रूप से स्थापित अथवा निगमित है और अपने गृह देश में पूर्व स्नातक परास्नातक और उच्च स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है (ii) जो पांचपरिक रूप से आमने—सामने डिग्री प्रदान कराने वाली शिक्षा प्रदान कराता है लेकिन दूरस्थ, ऑन लाईन और ओडीएल विधि को उपयोग में नहीं लाता।
- 1•15 "भावहरण (साहित्यिक चोरी)"** से अभिप्राय है किसी अन्य के कार्य या भावों की चोरी करना और फिर उन्हें अपना बताकर प्रस्तुत करना।
- 1•16 "अनुबन्ध शिक्षण स्टाफ"** से अभिप्राय है अंश—कालिक अथवा आकस्मिक अनुदेशक लेकिन ऐसा पूर्णकालिक शिक्षण स्टाफ नहीं जिसे गुरु गोबिन्द सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु किराये पर लिया जाये।
- 1•17 "पर्यवेक्षक"** से अभिप्राय होगा इस अध्यादेश में अनुबंधितानुसार विश्वविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालय के अर्हता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण सदस्य।
- 1•18 "सह—पर्यवेक्षक"** ये अभिप्राय है इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत शोध—छात्र के लिये समनुदेशित अतिरिक्त पर्यवेक्षक।
- 1•19 "स्कूल शोध समिति (एस आर सी/स्कूल्शो•स०)** "का अर्थ है एक ऐसी स्कूल शोध समिति जिसमें संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में और स्कूल के माध्यम से दर्शन निष्णात कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये विषयों(०) के विश्वविद्यालय से जुड़े सभी मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक समिलित होंगे। बहुविधि विषयों में दर्शन निष्णात की उपाधि प्रस्तावित करने वाले स्कूल्स में प्रत्येक ऐसे विषय, जैसी आवश्यकता हो, के लिये अलग से स्कूल शोध समिति होनी चाहिये, साथ ही इस प्रकार की समितियों में संबंधित विषयों के न्यूनतम तीन सदस्य होने चाहिये। इसके अतिरिक्त संबंधित स्कूल की ऐसी सभी विषय—विनिर्दिष्ट स्कूल शोध समितियों में न्यूनतम दो समान सदस्य होने चाहिये इसमें पारिभाषिक शब्द 'एस आर सी' केन्द्र की केन्द्रीय शोध एवं परामर्शी समिति (सी आर सी सी) के संबंध में भी लागू होगा। सी आर सी सी की भूमिका, उपरोक्त विवरणानुसार एस आर सी की भूमिका के समान ही होगी, जो अध्यादेश 35 में विवरणित इसकी अपनी भूमिका के अतिरिक्त होगी। इसके बाद, अध्यादेश में जहाँ कहीं भी एस आर सी शब्दावली का उपयोग होगा, उसे अध्यादेश 35 के अन्तर्गत गठित केन्द्र के संदर्भ में सी आर सी के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिये।
- 1•20 "बाह्य परीक्षक"** से अभिप्राय प्रकाशित शोधकार्य धारक एक ऐसा विद्वान् (अकादमिक सदस्य) / शोधकर्ता, जो उस विश्वविद्यालय का भाग नहीं होगा जिसमें दर्शन निष्णात कार्यक्रम के लिये दर्शन निष्णात शोधकर्ता ने स्वयं को पंजीकृत कराया हुआ है तथा जैसा भी इस अध्यादेश में और भी अधिक वर्णित हैं।
- 1•21 "आयोग"** से इस अध्यादेश में अभिप्रेत होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
- 1•22 "सैट"** का अर्थ होगा दर्शन निष्णात प्रवेश परीक्षा (सीईटी—कॉमन एन्ट्रेंस टैस्ट समान योग्यता परीक्षा) जिसका संचालन विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा किया जायेगा।
- टिप्पणी:** इस अध्यादेश में जहाँ कहीं भी 'वह (ही)' और 'उसका (हिज़)' शब्द आया है, इसका क्रमशः निहितार्थ होगा 'वह (पु.)/वह (स्त्री.)' तथा 'उसका/उसकी'।
- 2•0 दर्शन निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता मापदण्ड**
- 2•1** दर्शन निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी के पास निष्णात उपाधि हो अथवा वह किसी तदनुरूप सांविधिक नियामक निकाय द्वारा निष्णात उपाधि के समरूप घोषित व्यावसायिक उपाधि, सकलता में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा वि.वि. अनुदान आयोग—7 अंक मान में इसके समरूप श्रेणी 'ख' (अथवा जहाँ भी श्रेणीकरण प्रणाली अस्तित्व में है वहाँ अंकमान के समरूप श्रेणी) अथवा शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों को आश्वस्त करने, मूल्यांकन करने अथवा प्रत्यायन करने के उद्देश्य से उस देश में किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण अथवा उसके मूल देश की विधि के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित प्राधिकार द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त अथवा प्राधिकृत मूल्यांकन तथा प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित विदेशी शिक्षण संस्थान से समतुल्य उपाधि धारक हो।

**2•2** समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ—साथ अनु०जाति / अनु०ज०जाति / अन्य पिछड़े वर्ग (गैर नवोन्नत वर्ग/दिव्यांगजन/आर्थिक दुर्बल वर्ग (ई डब्ल्यू एस) से संबंधित अभ्यर्थियों को पाँच (5) प्रतिशत अंकों अथवा उसके समतुल्य श्रेणी की छूट अनुमत होगी।

### 3•0 प्रवेश प्रक्रिया

- 3•1** अध्ययनों के दर्शन निष्पात कार्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा (सामा०प्र० परीक्षा—सीईटी) के माध्यम से होगा।
- 3•2** दर्शन निष्पात के लिये विशिष्ट विद्या विशेष में उपलब्ध रिक्तियों (सीटों) की संख्या, दर्शन निष्पात कार्यक्रम में प्रवेश के लिये जारी की गयी प्रवेश विवरणिका का ही भाग होगी। लिखित प्रवेश परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम, सम्बन्धित स्कूल द्वारा, प्रवेश विवरणिका में समाविष्ट करने के लिये, अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- 3•3** दर्शन निष्पात कार्यक्रमों के लिये विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों जिसमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित कराना होंगे।
- 3•4** दर्शन निष्पात कार्यक्रम में प्रवेश के लिये, प्रवेश विवरणिका में, रिक्तियों की संख्या, प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेशार्थ प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा(एँ) आयोजित किये जाने वाले केन्द्र और अभ्यर्थियों के हितार्थ अन्य सभी संबंधित सूचनाएँ प्रदान की गयी होंगी।
- 3•5** आरक्षण, राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ही होगा, जिसे समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- 3•6** दर्शन निष्पात कार्यक्रमों के लिये विज्ञापन और विवरणिका अनु०वि०प्रको० (आर०डी०सी) द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे और वि०वि० के कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् इन्हें सार्वजनिक कर दिया जायेगा।
- 3•7** दर्शन निष्पात कार्यक्रम में प्रवेश के लिये सामा०प्र० परी० (सीईटी) में सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ लिखित प्रवेश परीक्षा अर्हक होगी। अनु० जाति / जनजाति/अन्य पि०जाति / दिव्यांग श्रेणी/आर्थिक रूप से दुर्बल (ई डब्ल्यू एस०) और समय—समय पर आयोग के निर्णयानुसार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची निकाली जायेगी।
- 3•8** इसी योग्यता क्रमसूची से, आरक्षण आधारानुसार सभी श्रेणियों से प्रत्येक विद्यमान रिक्ति के लिये 3 अभ्यर्थियों के अनुपात में साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
- 3•9** सामा०प्र०परी० और साक्षात्कार में संचयी प्रदर्शन आधार पर ही अंतिम परिणाम घोषित किया जायेगा। अंकों का महत्त्व सामा०प्र०परी० के लिये 90 प्रतिशत और साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत होगा।
- 3•10** साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा संबंधित विभागों / स्कूलों की 'प्रवेश समिति' द्वारा आयोजित किये जायेंगे।
- 3•11** संबंधित स्कूल की संबद्ध स्कूल शोध समिति, आर सी आई मार्ग निर्देशों के अनुसार पाठ्य समिति के माध्यम से विस्तृत पात्रता मापदण्ड परिभाषित करेगी जिन्हें कम से कम इस अध्यादेश के विनिर्देशों की आनुरूप्यता में होना चाहिये और कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् उसे प्रवेश विवरणिका में समाहित करने के लिये अनु०वि०प्रको० (आर डी सी) के पास भेज दिया जायेगा।
- 3•12** संबंधित स्कूल की संबद्ध शोध समिति, आर सी आई मार्ग निर्देशों के अनुसार पाठ्य समिति के माध्यम से स्कूल को उन विद्या विशेष को विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें दर्शन—निष्पात कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। और उन्हें कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् प्रवेश विवरणिका में समाहित करने के लिये आर डी सी के पास भेज दिया जायेगा। अध्ययन का विद्या विशेष (दर्शन निष्पात) केवल एक ही स्कूल द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। यदि अनेक स्कूल अध्ययन के उसी विद्या विशेष को प्रस्तावित करने के इच्छुक होंगे तो कुलपति महोदय वह विद्या विशेष किसी खास स्कूल को आवंटित कर देंगे। कुलपति महोदय का यह निर्णय अंतिम होगा।

- 3•13** विश्वविद्यालय की आर डी सी सभी पंजीकृत दर्शन निष्णात छात्रों की सूची वर्षानुक्रम में अपनी वैबसाइट पर अनुरक्षित करेगी। इस सूची में पंजीकृत छात्र का नाम/उनके अपने शोध का क्षेत्र/उनके अपने पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि सम्मिलित होंगे।
- 3•14** विश्वविद्यालय स्कूलों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के ऐसे स्थायी शिक्षण सदस्यों सहित नियोजित अभ्यर्थियों, जो दर्शन निष्णात में पूर्णकालिक शोध छात्र के रूप में प्रवेश लेने के इच्छुक होंगे, को विश्वविद्यालय को न्यूनतम पंजीकरण अवधि के पालन हेतु न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिये अवकाश लेना होगा। अपने नियोजकों से अवकाश प्राप्त करने के लिये जिन अभ्यर्थियों को चयन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वे इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वैबसाइट पर प्रदर्शित चयन/प्रवेश सूची का उपयोग कर सकेंगे परन्तु, प्रवेश की स्वीकृति केवल अवकाश मंजूरी पत्र की मूल प्रति जमा कराने के बाद ही प्रदान की जायेगी। नियमित नियोजन में नियोजित सभी अभ्यर्थियों (पूर्ण कालिक) को दर्शन निष्णात कार्यक्रम के अनुपालन के उद्देश्य से अपने नियोजन संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “निरापत्ति प्रमाण पत्र” जमा कराना होगा, यह प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय जमा कराना होगा।
- 4•0** **कार्यक्रम की अवधि (पंजीकरण कालावधि)**
- 4•1** दर्शन निष्णात कार्यक्रम, पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम दो (2) वर्ष की अवधि का होगा।
- 4•2** महिला शोध छात्रों तथा निःशक्त व्यक्तियों (40 % से अधिक निःशक्तता धारियों) को एक (1) वर्ष की अधिकतम अवधि में छूट अनुमत होगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को समूची दर्शन निष्णात अवधि में केवल एक बार ही मातृत्व अवकाश/शिशु-देखभाल छुट्टी केवल 240 दिन के लिये ही सुलभ करायी जा सकेगी। अवकाश की इस अवधि की गणना, दर्शन निष्णात की अवधि गणना के उद्देश्य से नहीं की जायेगी।
- 4•3** दर्शन निष्णात हेतु विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक एक वर्ष तक का अधिकतम विस्तार (उपरोक्त खण्ड 4•2 की आनुरूप्यता में, उपरोक्त खण्ड 4•1 के अनुसार) सम्बन्धित स्कूल के स्कूल शो० समि० (एस आर सी) द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे आगे, यदि कोई हो तो, अधिकतम एक वर्ष के विस्तार के लिये शोधकर्ता द्वारा विलम्ब के लिये लिखित में औचित्य प्रस्तुत करना होगा तथा पर्यवेक्षक इसे विचारार्थ, एस आर सी को अग्रेषित करेंगे। एस आर सी लिखित में अभिलिखित कारणों पर विचार करते हुए विस्तार को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में दर्शन निष्णात को पूरा करने की अवधि में अधिकतम विस्तार (उपरोक्त खण्ड 4•2 की आनुरूप्यता में खण्ड 4•1 के अनुसार) दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
- 4•4** यदि कोई शोध छात्र/छात्रा अपने शोध प्रबंध को अनुबंधित समय-सीमा में जमा नहीं करा पाता/पाती है तो उसका पंजीकरण/प्रवेश रद्द हो जायेगा।
- 4•5** **उपस्थिति**
- 4•5•1** अध्ययन का पाठ्यक्रम, जब तक कि विशेष छूट प्राप्त न कर ली गयी हो, निरंतर रूप से जारी रहना चाहिये। पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान रूग्णावस्था अथवा किसी अन्य असाधारण परिस्थिति के कारण, छात्र की उपस्थिति में आ रही अड़चन की सूचना, संस्थान प्रमुख/संबंधित प्राधिकारी को प्रदान की जानी चाहिये और अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिये। किसी भी परिस्थिति में, पाठ्यक्रम नामांकन वर्ष से 4 वर्षों के अंदर निपट जाना चाहिये।
- 4•5•2** संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत (शिक्षण वर्ष में) उपस्थिति होनी चाहिये।
- 4•5•3** दो वर्ष की अध्ययन अवधि में, तीस दिन का कुल आकस्मिक अवकाश, एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अवकाश अनुमत होगा।
- 5•0** **पर्यवेक्षक:** पर्यवेक्षक, सहपर्यवेक्षक के रूप में मान्यता हेतु पात्रता मापदण्ड, तथा प्रत्येक पर्यवेक्षक के अधीन अनुमेय, दर्शन निष्णात छात्रों की संख्या का निर्धारण आदि आर सी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- 6•0** **पाठ्यक्रम कार्य :** क्रेडिट अपेक्षाएँ, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, निपटाना हेतु न्यूनतम मानक आदि।

- 6•1** दर्शन निष्णात हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम कार्य आर सी आई की दिशा निर्देशानुरूप्यता में संबंधित एस आर सी द्वारा अभिकल्पित और संस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित विद्याविशेष के बीओएस द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- 6•2** दर्शन निष्णात पाठ्यक्रम कार्य हेतु निर्धारित सभी पाठ्यक्रम आकलन, निरंतरता आनुदेशिक अपेक्षाओं (क्रेडिट आर इंस्ट्रॉक्शनल रिकवारमेंट) की अनुरूपता में होंगे और वर्ण्य विषय, अनुदेशानात्मक एवं मूल्यांकन विधियों का विशेष विवरण देंगे।
- 6•3** दर्शन निष्णात कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि वे अपने प्रवेश लेने वाले शैक्षिक सत्र से दो शिक्षण वर्ष के दौरान एस आर सी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य को निपटायें। यदि कोई शोधार्थी किसी भी पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र में असफल रह जाता है तो बाद में जब भी कभी भी पाठ्यक्रम/परीक्षा आयोजित होंगे तो शोधार्थी उसमें पुनर्सम्मिलित होंगे।
- 6•4** दर्शन निष्णात कार्यक्रम के लिये, अध्ययन योजना एवं कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा निर्दिष्ट दर्शन निष्णात उपाधि प्रदान किये जाने के लिये अपेक्षाएँ पूर्ण कर दिये जाने पर, उपाधि (डिग्री) प्रदान कर दी जायेगी।
- 6•5** पाठ्यक्रम कार्य के लिये श्रेणीकरण प्रणाली और डिवीज़न्स, विश्व-विद्यालय के अध्यादेश-11 में यथा निर्दिष्टानुरूप ही होंगे। पाठ्यक्रम कार्य के प्रत्येक प्रश्न पत्र/ विषय के अधिकतम 100 अंक होंगे। आर सी आई मार्ग निर्देशों की अनुरूप्यता में शिक्षकों के सतत मूल्यांकन घटक 30 अंकों के होंगे और अन्तिम अवधि सत्र परीक्षा घटक के अंक 70 होंगे।
- 6•6** प्रत्येक विषय के लिये 30 अंक का शिक्षक द्वारा सतत मूल्यांकन उस संबंधित शिक्षक द्वारा किया जायेगा जिसे एस आर सी द्वारा विषय का दायित्व सौंपा गया है। संबंधित शिक्षक, सत्र समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपनी अंक तालिका अधिष्ठाता (डीन) के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को सूचित कर देंगे। शेष 70 अंकों के लिये परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा का आयोजन करेंगे। पाठ्य समिति द्वारा अनुमोदित प्राशिनिकों की नामिका, परीक्षा नियंत्रक को सूचित कर दी जायेगी। शिक्षक सतत मूल्यांकन एवं अंत अवधि सत्रक परीक्षा के अंकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। सत्रक-अवधि 15 सप्ताह होगी।
- 6•7** एक दर्शन निष्णात शोधार्थी को कार्यक्रम जारी रखने के लिये और शोध निबन्ध जमा करने की पात्रता प्राप्त करने के लिये, विषय/पाठ्यक्रम में न्यूनतम 'बी+ श्रेणी' अर्जित करनी होगी। यदि शोधार्थी न्यूनतम श्रेणी अर्जित नहीं कर पाता तो उसे विश्वविद्यालय/ आर सी आई के अनुप्रयोज्य विनियमों/ मार्ग निर्देशों के अनुसार एक या अधिक पाठ्यक्रम परीक्षा/विषय(ों) में पुनः सम्मिलित होना होगा। लागू पुनर्सम्मिलित शुल्क विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं के लिये अधिसूचितानुरूप ही होगा।
- 7•0** **मूल्यांकन एवं निर्धारण विधि, उपाधि प्रदान किये जाने हेतु न्यूनतम मानक/ क्रेडिट आदि।**
- 7•1** विषय कार्य के लिये क्रेडिट सम्मिलित करते हुए सकल न्यूनतम क्रेडिट, दर्शन निष्णात उपाधि प्रदान करते हेतु सुसंगत एस आर सी द्वारा यथा अनुमोदित आर सी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। इन्हें, कार्यक्रम की परीक्षा—योजना और पाठ्यक्रमानुसार ही परिभाषित किया जायेगा।
- 7•2** विषय कार्य के संतुष्टि पूर्ण निष्पादन तथा 6•7 उपरोक्त 6•7 उपरोक्त में निर्धारित अंक/श्रेणी अर्जित करने, जैसा भी मामला हो, के उपरान्त दर्शन निष्णात शोधार्थियों से अपेक्षा है कि वे शोध कार्य करें और उपरोक्त खण्ड-4 की अनुरूप्यता में तथा दर्शन निष्णात कार्यक्रम की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में यथा अनुबंधितानुसार उपयुक्त समयावधि में शोध निबंध का प्रारूप प्रस्तुत करें।
- 7•3** विषय कार्य के संतुष्टि पूर्ण निष्पादन तथा 6•7 उपरोक्त में निर्धारित अंक/श्रेणी अर्जित करने, जैसा भी मामला हो, के उपरान्त दर्शन निष्णात शोधकर्त्ताओं से अपेक्षा है कि वे शोधकार्य करें/ उपरोक्त खण्ड-4 के अंतर्गत अनुबंधितानुसार उपयुक्त समयावधि में शोध निबंध का प्रारूप प्रस्तुत करें।
- 7•4** एस आर सी, भावहरण (साहित्यिक चोरी) और अन्य प्रकार के अकादमिक छल—कपट ढूँढ़ निकालने के लिये अत्यधिक विकसित सॉफ्टवेयर एवं गैजेट्स का उपयोग करते हुए एक तंत्र विकसित करेंगे। जब मूल्यांकन के लिये शोध—निबंध प्रस्तुत किया जा रहा होगा तो शोध निबंध में शोध छात्र की ओर से एक वचनबंध होगा और शोध पर्यवेक्षक की ओर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी होगा कि यह कार्य मौलिक है। इसमें किसी भी प्रकार का भावहरण नहीं है। इस संस्थान् में जहाँ कार्य निष्पादित किया गया

था, उस संस्थान् अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा को प्राप्त करने के लिये यह कार्य, किसी को भी नहीं दिया गया है।

- 7•5 किसी भी शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत दर्शन निष्णात शोध निबंध को उसके अपने शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक से मूल्यांकन कराना चाहिये जो विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सम्बद्ध संस्थान में सेवारत नहीं हैं। मौखिक परीक्षा जो कि अनेक प्रश्न समेटे होगी, मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गयी समीक्षा भी सम्मिलित होगी दोनों के द्वारा एक साथ ही संचालित की जायेगी।
- 7•6 दर्शन निष्णात शोध का बचाव करने के लिये शोध छात्र की मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जायेगी यदि शोध/ शोधपत्र पर बाह्य परीक्षक(१) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक है और मौखिक परीक्षा लिये जाने की विशेष संस्तुति उसमें सम्मिलित है। यदि दर्शन निष्णात शोध दोनों बाह्य परीक्षकों द्वारा रद्द कर दी जाती है तो बिना किसी आगामी कार्रवाई के वह शोध स्वतः ही रद्द हो जायेगी और शोध छात्र को उपाधि ग्रहण करने का अपात्र समझा जायेगा। यदि दर्शन निष्णात शोध पत्र के संबंध में बाह्य परीक्षक की रिपोर्ट असंतोष जनक पायी जाती है और मौखिक परीक्षा की संस्तुति नहीं की गयी है तो संस्थान, शोध/ शोधपत्र को परीक्षकों की स्वीकृत नामावली के बाहर के किसी बाह्य परीक्षक को भेज देंगे। यदि बाद के परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक आती है तो मौखिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। यदि बाद के परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक आती है तो शोध/ शोधपत्र को रद्द कर दिया जायेगा और शोध छात्र को उपाधि (डिग्री) प्राप्त किये जाने का अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

#### **7•7 दर्शन निष्णात परीक्षकों की नियुक्ति**

- 7•7•1 दर्शन निष्णात शोध पत्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से पर्यवेक्षक, शोध कार्य के क्षेत्र में कम से कम 8 ऐसे विशेषज्ञों, की सूची प्रस्तुत करें, जिनके पास पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्ति हेतु अपेक्षित तुल्य अर्हता हो; जिसको विद्याशाखा डिसीप्लिन को स्कूल शोध समिति से अनुमोदन मिल जाये। स्कूल शोध समिति पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी नाम को जोड़ सकती है या काट सकती है। प्रत्येक परीक्षक से संबंधित पूर्ण संपर्क विवरण पत्राचार पता, ईमेल, दूरभाष/ चलभाष, फैक्स आदि उपलब्ध कराने का दायित्व पर्यवेक्षक का होगा।
- 7•7•2 कोई भी परीक्षक न तो उस संस्थान से संबंधित हो सकता है जिसमें शोध छात्र नियोजित है और न ही उस संस्थान से, जिसमें शोध छात्र के पर्यवेक्षक अथवा सह—पर्यवेक्षक जुड़े हुए हैं। साथ हीं, शोध छात्र के सहयोगी अथवा सहलेखक या संबंधित दर्शन निष्णात के शोध कार्यकाल में रहा उसका पर्यवेक्षक / सह—पर्यवेक्षक एक परीक्षक नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करने का दायित्व शोधकर्ता के पर्यवेक्षक और/ या सह—पर्यवेक्षक का होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि पर्यवेक्षक / सह—पर्यवेक्षक ने शैक्षिक नैतिकता के इस मानक का अनुरक्षण नहीं किया है तो स्कूल शोध समिति को, संबंधित पर्यवेक्षक / सह—पर्यवेक्षक द्वारा कम से कम तीन वर्ष तक शोध छात्रों का पंजीकरण करने से विवर्जित करने के लिये संस्तुत कर सकेगी। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
- 7•7•3 स्कूल शोध समिति से द्वारा अनुमोदित शोध पत्र के प्रस्तुति पूर्व सार तत्व और अंतिम—शीर्षक की प्राप्ति पर स्कूल शोध समिति से अध्यक्ष, संबंधित स्कूल शोध समिति परीक्षक सूचिका तथा प्रस्तुति पूर्व सार तत्व परीक्षण को उपरोक्त दस्तावेज प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर —भीतर भेज देंगे। इन शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिये उक्त सूचिका से बाह्य शोध प्रबंध मूल्यांकक(१) की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी। परीक्षक—सूचिका में कुलपति और नाम भी जोड़ सकते हैं।
- 7•7•4 दर्शन निष्णात शोध के मूल्यांकन हेतु कार्य रीतियों का अनुसरण परीक्षा प्रभाग कुलपति द्वारा अनुमोदन की अनुरूपता में करेगा।

#### **7•8 दर्शन निष्णात शोध प्रबंध का मूल्यांकन**

- 7•8•1 प्रत्येक परीक्षक से अनुरोध किया जायेगा कि वे शोध प्रबंध प्राप्त होने की तिथि से 06 सप्ताह के अन्दर, निर्धारित प्रपत्र (परीक्षा प्रभाग द्वारा अभिकल्पित तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत) पर विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन और अपनी अनुशंसाएँ परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करें।

**7•8•2** ऐसी परिस्थिति में, जबकि शोध प्रबन्ध का प्रेषण तिथि से 3 मास के अन्दर परीक्षक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दर्शन निष्णात शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये, परीक्षकों की अनुमोदित सूचिका से कुलपति किसी अन्य परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं।

**7•8•3** परीक्षक से अपेक्षा होगी कि वे सुनिश्चित/सुस्पष्ट ढंग से यह सूचित करें कि क्या उनके मतानुसार दर्शन निष्णात शोध प्रबन्धः

- (क) दर्शन निष्णात उपाधि को (मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा
- (ख) दर्शन निष्णात उपाधि (सुझाये गये बदलावों को समिलित किये जाने की शर्त और मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा
- (ग) संशोधित प्रपत्र पर पुनर्प्रस्तुति, अथवा
- (घ) अस्वीकृत

**7•8•4** दर्शन निष्णात शोध प्रबन्ध की पुनर्प्रस्तुति/अस्वीकरण की संस्तुति हेतु परीक्षक कारण दर्शायेंगे। यदि पुनर्प्रस्तुति की संस्तुति दर्शायी गयी है तो परीक्षक विशिष्ट रूप से उन आशोधनों को सुझायेंगे जिनका दर्शन निष्णात शोध प्रबन्ध में निर्वहन किया जाना, शोध छात्र के लिये आवश्यक है। स्कूल-अधिष्ठाता के परामर्श से परीक्षा नियंत्रक शोधार्थी और पर्यवेक्षक को उन सभी संशोधनों और आशोधनों की सूची उपलब्ध करायेंगे जो परीक्षक के परामर्शानुसार शोध प्रबन्ध में किये जाने अपेक्षित हैं।

**7•8•5** यदि भारी बदलाव किये जाने हैं और पुनर्प्रस्तुति/पुनर्मूल्यांकन की संस्तुति की गयी है तो परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में सूचना प्राप्त हो जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पर्यवेक्षक के परामर्श से शोध छात्र संशोधित वृतांत पुनर्प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, अपवादिक परिस्थितियों में स्कूल शो1 स0 स0 इस अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ा सकती है लेकिन यह सकल परिशोधन अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये संशोधित दर्शन निष्णात शोध उन्हीं परीक्षक(१) के पास मूल्यांकन के लिए भेज दिये जायेंगे जिन्होंने संशोधनों की संस्तुति की थी। यदि उनमें से कोई भी, संशोधित शोध की जांच करने से मना करते हैं तो स्वीकृत नामावली से अतिरिक्त परीक्षक की नियुक्ति कर दी जायेगी और उन्हें विगत परीक्षक (१) की टिप्पणियाँ भी सुलभ करायी जायेंगी जिससे कि संशोधित शोध के मूल्यांकन में उन्हें सुविधा रहे।

### **7•9 मौखिक प्रतिवाद / मौखिक परीक्षा**

**7•9•1** संतोषजनक दर्शन निष्णात शोध मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद एक शोध छात्र को, विधिवत रूप से गठित एक समिति, जिसे बाद में मौखिक प्रतिवाद समिति (ओडीसी) के नाम से उल्लिखित किया जायेगा, के समक्ष मौखिक रूप से अपने कार्य/शोध कार्य का समर्थन करना अपेक्षित होगा।

**7•9•2** मौखिक प्रतिवाद समिति (मो0प्र0समि0) में पर्यवेक्षक होंगे (कम से कम एक को उपस्थित रहना चाहिए) एक वे बाह्य परीक्षक जिन्होंने कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाने के बाद शोध का मूल्यांकन किया था यदि, शोध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक मौखिक प्रतिवाद आयोजित करने के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो स्वीकृत नामिका में से कुलपति महोदय एक वैकल्पिक परीक्षक की नियुक्ति कर देंगे।

**7•9•3** यदि आवश्यक समझा जाये, तो शोध छात्र के द्वारा उन्मुक्त मौखिक परीक्षा एवं प्रतिवाद, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से स्काइप/दृश्य दूर संलाप के माध्यम से आयोजित किये जा सकते हैं।

**7•9•4** मौखिक परीक्षा के चरम के साथ परीक्षा के सभी स्तरों की निष्पत्ति के बाद मौखिक प्रतिवाद समिति (मो0प्रति0समिति) निर्धारित प्रपत्र (परीक्षा प्रभाग द्वारा अभिकल्पित और परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत) पर अपनी रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से कुलपति को निम्न में से एक संस्तुति के साथ भेजेगी:

- (i) कि उपाधि (डिग्री) प्रदान कर दी जाये।

- (ii) कि शोधकर्ता को किसी बाद की तिथि पर नये सिरे से मौखिक प्रतिवाद के लिये प्रस्तावित किया जाये।
- (iii) कि उपाधि प्रदान न की जाये।

**7•9•5** मौ0 प्रति0 समि0 की अनुशंसाओं पर कुलपति का निर्णय परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के निर्णय की तिथि उद्धृत करते हुए अधिसूचित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दर्शन निष्णात की उपाधि के औपचारिक रूप से प्रदान किये जाने की प्रभावी तिथि के रूप में निर्धारित होगी। इस अधिसूचना से पूर्व, परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि शोध छात्र ने दर्शन निष्णात शोध प्रबंध की एक सॉफ्ट प्रति तथा दो हार्ड बाउंड प्रतियाँ, एक संबंधित स्कूल के पुस्तकालय के लिये और दूसरी विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये प्रदान कर दी हैं। इनमें पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक शुद्धियाँ/आशोधन सम्मिलित किये होने चाहिये और शोध प्रबंध के प्रारम्भ में एक पृथक पन्ने पर निम्न स्वत्वाधिकार प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये:

© गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, नयी दिल्ली—110078 सर्वाधिकार सुरक्षित।

**7•9•6** दर्शन निष्णात (एम0फिल) की समाप्ति की अधिसूचना के बाद अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा और दीक्षांत समारोह के समय अंतिम उपाधि प्रदान किये जाने के समय विश्वविद्यालय शोध छात्र को प्रमाण पत्र और डिग्री प्रदान करेगा जिसमें उस स्कूल और विद्याविशेष का उल्लेख होगा। जिसमें उसने दर्शन निष्णात किया है।

#### **8•0 पूर्ण कालिक पंजीकरण के रूप में दर्शन निष्णात का निरूपण**

- 8•1 दर्शन निष्णात कार्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।
- 8•2 नियोजित अभ्यर्थियों को पूर्णकालिक विधि से ही दर्शन निष्णात करने की अनुमति होगी जब कि इस अध्यादेश की अन्य सभी शर्तें पूरी होती हों।

#### **9•0 इनफिलबनेट (INFLIBNET) के साथ निष्केपागार**

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के पूर्वात् और दर्शन निष्णात उपाधि(यों) के प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व परीक्षा प्रभाग, दर्शन निष्णात शोध प्रबन्ध की एक इलैक्ट्रोनिक प्रति, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को उपलब्ध करायेगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष, उक्त प्रति इन्फिलबनेट को प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करेंगे।

- 10•0 इस अध्यादेश के अधिनियमन से पहले विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षकों की पात्रता की सम्बन्धित स्कूल शो0 स0 द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- 11•0 प्रवेश विवरणिका की तैयारी और जारी करने के लिये प्रचालन मार्ग दर्शिका निदेशक अनु सं0 तथा विकास प्रको0 द्वारा प्रस्तावित की जायेगी और कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् लागू कर दी जायेगी।
- 12•0 दर्शन निष्णात शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु प्रचालन मार्गदर्शिका परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावित की जायेगी और कुलपति महोदय के अनुमोदन—पश्चात् जारी कर दी जायेंगी।
- 13•0 इस अध्यादेश में किसी बात का उल्लेख न होने पर भी, यदि दर्शन निष्णात कार्यक्रम का नियमन करने वाले संविधिक निकाय किसी ऐसी रिथर्टि/विनिर्दिष्टता को परिभाषित करती है जो कि प्रवेश पात्रता अथवा प्रक्रिया से सम्बन्धित हो, जो कि इस अध्यादेश की विसंगति में हो तो वह तब तक कुलपति महोदय की स्वीकृति से अनुप्रयोज्य रहेंगी, जब तक कि उक्त नयी शर्तों/विनिर्देशों को सम्मिलित करते

हुए इस अध्यादेश में आवश्यक संशोधन नहीं कर किये जाते । संबंधित स्कूल शोध समिति इसकी समाविष्टि को प्रस्तावित करेगी ।

- 14•0 इस अध्यादेश में किसी भी ऐसी बात के न होते हुए भी किन्हीं अप्रत्याशित मुद्दों के उठ जाने और जो इस अध्यादेश की व्याप्ति में न हों अथवा व्याख्या में मतभेद होने की स्थिति में निदेशक, अनु० तथा विका० प्रको० स्कूलों के किसी अथवा सभी अधिष्ठाताओं से गठित समिति से मत/सलाह लेने के बाद कुलपति निर्णय ले सकेंगे । कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा ।

यह अध्यादेश, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये अनुमोदन की तिथि अर्थात् 25.06.2024 से लागू होगा ।

आदेशानुसार,  
डॉ० कमल पाठक, कुलसचिव

## GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2025

**F. No. GGSIPU/Coord/Ord.37/83rd BOM/2024/440.**— In pursuance of the provisions of Section 27 (1) (xi) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 83rd meeting held on 25.06.2024, vide agenda item no. 83.32 approved the new Ordinance 37 captioned 'Governing Programmes leading to the Degree of Master of Philosophy (M.Phil)' is notified as under:

### **Ordinance 37: Governing Programmes leading to the Degree of "Master of Philosophy (M.Phil.)"**

**Applicability :** This Ordinance shall apply to all programmes leading to the degree of M.Phil. in Clinical Psychology and Psychiatric Social Work (applicable from the Academic Session 2024-25). The Ordinance shall come into force from the date of approval of the Board of Management.

#### 1.0 Definitions

- 1.1 “**Act**” shall mean the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998, as amended from time to time.
- 1.2 “**University**” shall mean Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi.
- 1.3 “**School of Studies**”, also referred to as School(s) or University School of Studies (USS) shall mean Schools of Studies established by the University as per clause 1.0 of Ordinance 2.
- 1.4 “**Centre**” shall mean Centre of Excellence established by the University as per clause 1 of Ordinance 35.
- 1.5 “**College/Institute**” shall mean an academic institution maintained or admitted by the University to its privileges and includes an affiliated college/institute as defined in section 2(i) of the Act and approved for M.Phil. programme as per the provisions of this Ordinance.
- 1.6 “**Board of Studies (BOS)**” shall have the same meaning as the Board of School of Studies defined under clause 2 of Ordinance 2 of the (USS) concerned. The term 'Board of Studies' herewith shall also apply to the 'Steering Committee' of the Centre(s). The role of the Steering Committee shall be equivalent to the role of BOS as defined above in addition to its role defined in the Ordinance 35. Furthermore, the constitution of the Steering Committee shall be as defined in Ordinance 35. Wherever the term BOS is used in this Ordinance, hereafter, it should be read as 'Steering Committee' in the context of the Centre constituted under Ordinance 35.
- 1.7 “**RDC**” shall mean the Research and Development Cell of the University.
- 1.8 “**Course Work**” means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the M.Phil. Degree

- 1.9   **“COE”** shall mean the Controller of Examinations of the University.
- 1.10   **“Discipline”** shall mean the discipline(s) in which the M.Phil. degree is awarded as mentioned in the M.Phil. degree certificate. The SRC shall recommend and BOS of the concerned School shall approve the discipline(s) in which M.Phil. Degree shall be offered through the School. The Dean of the concerned School shall communicate the discipline(s) in which M.Phil. Programme is offered in the School, after approval of the BOS, to the RDC for notification.
- 1.11   **“Academic Session”** shall be of one-year duration apportioned into two semesters of six months. The Academic Session shall ordinarily commence from the first working day of the month of August every year. The RDC shall notify the detailed academic calendar for the conduction of the coursework part of the M.Phil. programme while the academic calendar for the review of M.Phil. dissertation/thesis work shall be notified by the concerned SRC.
- 1.12   **“Research Scholar”** shall mean a person registered for M.Phil. under the provisions of this ordinance, also called “scholar”.
- 1.13   **“Foreign Research Scholar”** shall mean foreign nationals or persons of Indian origin registered for M.Phil. as a research scholar, under the provisions of this ordinance.
- 1.14   **“Foreign Educational Institution”** means—(i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode.
- 1.15   **“Plagiarism”** means the practice of taking someone else’s work or idea and passing them as one’s own.
- 1.16   **“Adjunct Faculty”** means a part-time or contingent instructor, but not a full-time faculty member hired to teach by Guru Gobind Singh Indraprastha University.
- 1.17   **“Supervisor”** shall mean a qualified and recognized faculty member of the University or affiliated college as stipulated in this Ordinance.
- 1.18   **“Co-Supervisor”** shall mean an additional “supervisor” assigned to a “research scholar” under the provisions of this Ordinance.
- 1.19   **“SRC”** shall mean the School Research Committee, consisting of the Dean of the concerned School as the Chairperson, and all recognized supervisors of the University in the discipline(s) in which the M.Phil. programme is offered through the School. The Schools that offer M.Phil. degree in multiple disciplines may have a separate SRC for each such discipline as needed, provided that each such SRC has no less than three members from the concerned discipline. In addition, there should be at least two common members in all such discipline-specific SRCs of the concerned School. The term ‘SRC’ herein shall also apply to the ‘Centre Research and Consultancy Committee’ (CRCC) of a Centre. The role of CRCC shall be equivalent to the role of SRC as defined above, in addition to its role defined in the Ordinance 35. Further more, the constitution of CRCC shall be as defined in Ordinance 35. Wherever the term SRC is used in the Ordinance, hereafter, it should be read as CRCC in the context of the Centre constituted under Ordinance 35.
- 1.20   **“External examiner”** means an academician/researcher with published research work who is not part of the University where the M.Phil. scholar has registered for the M.Phil. programme, and as further detailed in this Ordinance.
- 1.21   **“Commission”** shall mean University Grants Commission in this Ordinance.
- 1.22   **“CET”** shall mean M.Phil. entrance test to be conducted by the Examination branch of the University.

**Note:** In this Ordinance wherever ‘He’ and ‘His’ occurs, these shall mean to imply ‘he/she’ and ‘his/her’, respectively.

## 2.0   **Eligibility criteria for admission to the M.Phil. Programme**

- 2.1   Candidates for admission to the M.Phil. programme shall have a Master’s Degree or a professional degree declared equivalent to the Master’s degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade ‘B’ in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing accrediting or assuring quality and standards of educational institutions. Master’s degree obtained by correspondence course, part-time course or by distance education will not be considered eligible for admission in M.Phil.

2.2 A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled/Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

### 3.0 **Procedure for Admission**

3.1 Admission to the M.Phil. programme of studies shall be through an Entrance Test (CET) conducted by the University.

3.2 The number of seats available in a particular discipline for M.Phil. shall be a part of the admission brochure issued for admission to the M.Phil. programmes. The detailed syllabus for the written entrance test shall be forwarded to the RDC for incorporation in the admission brochure by the concerned School.

3.3 The advertisement for M.Phil. programmes admission shall be in at least two national newspaper out of which at least one shall be in Hindi language.

3.4 The admission brochure for M.Phil. programmes shall specify the number of seats for admission, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.

3.5 Reservation shall be as per the State Reservation Policy, notified by the University from time to time.

3.6 The advertisement and the brochure for M.Phil. programmes shall be proposed by the RDC and after approval of the Vice-Chancellor of the University shall be put in public domain.

3.7 The written entrance test shall be qualifying for admission to M.Phil. programme with a minimum of 50% marks for the general category candidates in CET. A relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ differently-abled category/ Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time). A merit list will be drawn of the candidates who score the qualifying marks.

3.8 From this merit list, candidates shall be called for interview in the ratio of 3 candidates for each existing seat in all categories as per the reservation matrix.

3.9 The final result will be declared on the basis of cumulative performance in CET and interview. Weightage of marks will be 90% for CET and 10% for the interview.

3.10 The interview / viva-voce shall be conducted by the Admission Committee of the concerned department / School.

3.11 The relevant SRC of the concerned school shall define the detailed eligibility criterion through the BOS as per RCI guidelines, which minimally should be in consonance with the specification of this Ordinance and the same after approval of the Vice-Chancellor shall be communicated to the RDC for incorporation in the admission brochure.

3.12 The relevant SRC of concerned school shall specify the disciplines in which M.Phil. programmes are offered through the school through the BOS as per RCI guidelines, and the same after approval of the Vice-Chancellor shall be communicated to the RDC for incorporation in the admission brochure. A discipline of study (M.Phil.) shall be offered by only one school. If multiple schools desire to offer the same discipline of study, then the Vice-Chancellor shall allocate the discipline to a particular school, the decision of the Vice-Chancellor shall be final.

3.13 The RDC of the University shall maintain the list of all the M.Phil. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, area of his / her research, name of his / her supervisor / co-supervisor, date of enrolment / registration.

3.14 Employed candidates including permanent faculty members of the University Schools or affiliated colleges/institutions, who wish to seek M.Phil. admission as full-time research scholars, must obtain leave for a period of at least two years. Candidates who need proof of selection to obtain leave from their employers may use the selection/admission list displayed on the University website for this purpose, but admission shall only be granted upon submission of the leave sanction letter in original. All employed candidates (full-time), in regular employment must obtain a "No Objection Certificate" for the purpose of pursuing M.Phil. programme, the same must be submitted at the time of interview for admission.

### 4.0 **Duration (Registration Period) of the Programme**

4.1 M.Phil programme shall be for a duration of two years.

4.2 The women candidate and Persons with Disability (more than 40% disability) shall be allowed a relaxation of one year for M.Phil. in the maximum duration. In addition, the women candidates shall be provided Maternity Leave / Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil. for upto 240 days, this period of leave shall not be counted for the purpose of calculation duration of M.Phil.

- 4.3 An extension beyond the period specified for M.Phil. (as per clause 4.1 above, in consonance with clause 4.2 above) upto one year in the maximum duration may be granted by the SRC of the concerned school. Further extension, if any, not exceeding a period of one year shall require a written justification for the delay by the research scholar and the supervisor for the consideration of the SRC; the SRC for reasons recorded in writing may consider and approve the extension. In no case, extension of maximum duration of completion of M.Phil. (as per clause 4.1 above, in consonance with clause 4.2 above) can exceed two years.
- 4.4 If the research scholar is not able to submit his / her dissertation within the stipulated period, his / her registration / admission shall stand cancelled.

#### 4.5 **Attendance**

4.5.1 Course of the study must, unless special exemption is obtained, continuously be pursued. Any interruption in a candidate's attendance during the course of study, due to illness or other extraordinary circumstances must be notified to the Head of the Institution/concerned authority and permission should be obtained. Under any circumstances the course must be completed within 4-yr from the year of enrolment.

4.5.2 A minimum attendance of 80% (in the academic year) shall be necessary for taking the respective examination.

4.5.3 Thirty days of causal leave, maximum of fifteen days per academic year, shall be permitted during the two-year course period.

**5.0 Supervisors:** Eligibility criteria for recognition to be a Supervisor, Co-Supervisor, as well as number of M.Phil. Scholars permissible per Supervisor, etc shall be done as per the RCI guidelines.

**6.0 Course Work:** Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

6.1 The detailed course work for M.Phil. shall be designed and recommended by the concerned SRC and approved by the BOS of the concerned discipline in consonance with RCI guidelines.

6.2 All courses prescribed for M.Phil. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods.

6.3 All candidates admitted to the M.Phil. programmes shall be required to complete the coursework prescribed by the SRC during the two academic year from the academic session in which the scholar is admitted. If a scholar fails in any course/paper, the scholar shall reappear as and when the course/paper examination is scheduled subsequently.

6.4 For the M.Phil. programme on completion of the requirement for the award of the M.Phil. Degree, as specified in the scheme of study and the syllabi of the programme, the degree shall be awarded.

6.5 The grading system and divisions for the course work shall be as specified in the Ordinance 11 of the University. Each paper / course of the course work shall be of maximum 100 marks. The Teacher's Continuous Evaluation component shall be of 30 marks and End-Term Semester Examination component shall be of 70 marks in consonance with RCI guidelines.

6.6 The teacher's continuation evaluation of 30 marks, for every course shall be conducted by the concerned faculty who is allocated the responsibility of teaching the course by the SRC. The concerned faculty shall communicate their marks to the Controller of Examinations through the Dean, within a week of the completion of the semester.

For the rest 70 marks, the Controller of Examinations shall conduct the examination. The panel of paper setter, as approved by the BOS shall be communicated to the Controller of Examinations. The Controller of Examinations shall declare the result combining the teacher's continuation evaluation and the end-term semester examination. The duration of the semester shall be of 15 weeks.

6.7 A M.Phil. scholar has to obtain a minimum of B+ grade in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the dissertation. If, a scholar does not obtain the minimum grade, the scholar may reappear in one or more course work paper/courses as per applicable regulations / guidelines of the University / RCI. The reappear fee applicable shall be as notified for other examinations of the University.

#### 7.0 **Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.**

7.1 The overall minimum credit requirement, including credit for the course work, for the award of M.Phil. degree shall be as per RCI guidelines as approved by the relevant SRC. The same shall be defined in the Scheme of Examination and Syllabi of the programme.

7.2 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 6.7 above, as the case may be, the M.Phil. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation within a reasonable time, as stipulated in this Scheme of Examination and Syllabi of the M.Phil. programme and in consonance with clause 4 above.

- 7.3 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clause 6.7 above, as the case may be, the M.Phil. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation within a prescribed time, as stipulated in this Ordinance under clause 4 above.
- 7.4 The SRC shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.
- 7.5 The M.Phil. Dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the University or any of its Affiliated Institutions. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by both of them together.
- 7.6 The viva-voce of the research scholar to defend the M.Phil. dissertation shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. In case, the M.Phil. dissertation is rejected by both the external examiners, then the thesis shall stand rejected without any further action and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree. If the evaluation report of the external examiner in case of M.Phil. dissertation, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the Institution shall send the dissertation/thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the later examiner is satisfactory. If the report of the later examiner is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

#### **7.7 Appointment of Examiners for M.Phil. Dissertation**

- 7.7.1 For the purpose of evaluation of M.Phil. dissertation, the supervisor shall submit a list of at least eight experts in the subject area of research work, who possess requisite qualification equivalent to the requirement for recognition of a supervisor, for the approval of the SRC of the discipline. The SRC may add or delete any of the name(s) proposed by the supervisor(s). The supervisor shall be responsible to provide the full contact details of each of the examiners, including postal address, email, phone, fax, etc.
- 7.7.2 An examiner cannot be from the same institution where the research scholar is employed, or from the institution to which the supervisor and/or joint supervisor of the research scholar belongs. Further, a collaborator or co-author of the research scholar or his/her supervisor or joint supervisor during the tenure of the concerned M.Phil. research scholar cannot be an examiner. The responsibility for ensuring this shall lie on the Supervisor / Co-Supervisor of the scholar. In case, it is found the supervisor / co-supervisors have not maintained this standard of academic ethics, the SRC may recommend for debarment of concerned supervisor / co-supervisor for further registration of scholars for a minimum period of three years to the Vice-Chancellor. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.
- 7.7.3 On receipt of the final title and pre-submission synopsis of the thesis approved by the SRC, the Chairperson of the SRC shall send the panel of examiners as approved by the concerned SRC, to the COE, within a week. The Vice Chancellor shall appoint the external thesis evaluator(s) from the above panel for evaluation of the thesis. The Vice-Chancellor may add names to the panel of examiners.
- 7.7.4 The Examination Division will follow the modalities for the evaluation of the M.Phil. Dissertation as approved by the Vice Chancellor.

#### **7.8 Evaluation of the M.Phil. Dissertation**

- 7.8.1 Each examiner will be requested to submit to the COE, a detailed assessment report and his/her recommendations on a prescribed proforma (designed by the Examinations Division and approved by the Controller of Examinations) within 06 weeks from the date of receipt of the thesis.
- 7.8.2 In the event that the assessment report is not received from an examiner within 3 months from the date of dispatch of the thesis, the Vice Chancellor may appoint another examiner from the approved panel of examiners for evaluating the M.Phil. dissertation.
- 7.8.3 The examiner shall be required to state categorically whether in his opinion, the M.Phil. dissertation should be:
- accepted for the award of M.Phil. (after oral defence), or
  - accepted for the award of M.Phil. degree (subject to incorporation of changes suggested and after oral defence), or
  - resubmission in the revised form, or

(d) rejected

- 7.8.4 The examiner shall state the reasons for recommending resubmission/rejection of the M.Phil. dissertation. If resubmission is recommended, the examiner shall specifically indicate the modifications that need to be made in the M.Phil. dissertation by the research scholar. The COE in consultation with the Dean of the School shall also provide to the research scholar and supervisor, a list of all corrections and modifications required in the thesis, as suggested by the examiners.
- 7.8.5 If the corrections are major and resubmission/re-evaluation has been recommended, the research scholar may resubmit the revised version in consultation with the supervisor, within a period of one year from the date of communication in this regard from the COE. However, in exceptional circumstances, this period may be extended by SRC by one more year but the total revision time shall not exceed two years. The revised M.Phil. dissertation shall be sent for assessment to the same examiner(s) who recommended revision. In the event of any of them declining to examine the revised thesis, additional examiner may be appointed from the approved panel, and provided with the comments of the previous examiner(s) to facilitate the evaluation of the revised thesis.

#### **7.9 Oral Defence / Viva-Voce**

- 7.9.1 A research scholar, after receiving a satisfactory M.Phil. dissertation evaluation report, shall be required to defend his/her work/thesis orally before a duly constituted committee, herein after referred to as Oral Defence Committee (ODC).
- 7.9.2 ODC shall consist of the supervisor(s) (at least one must be present), and one external examiner who evaluated the thesis to be appointed by the Vice Chancellor. If none of the examiners who evaluated the thesis is available for the conduct of the oral defence, an alternative examiner from the panel of approved examiners shall be appointed by Vice Chancellor.
- 7.9.3 The Viva Voce and the defence by the research scholar may also be done through Skype/Video conferencing, if required, with prior approval of the Vice Chancellor.
- 7.9.4 On completion of all the stages of examination culminating with the Viva Voce, the ODC shall submit its report in the prescribed proforma (designed by the Examinations Division and approved by the Controller of Examinations) to the Vice Chancellor through the COE recommending any one of the following:
- (i) that the degree be awarded,
  - (ii) that the research scholar be subjected to a fresh Oral Defence at a later date,
  - (iii) that the degree be not awarded.

- 7.9.5 The decision of the Vice Chancellor on the recommendations of the ODC shall be notified by the COE, mentioning the date of the decision of the Vice Chancellor, which shall be construed as the effective date of the award of the M.Phil degree, subject to the formal award during the University convocation. Prior to this notification, the COE shall ensure that the research scholar has submitted a soft copy of the M.Phil. dissertation and two hard bound copies, one for the library of the concerned School and one for the central library of the University. These should incorporate all necessary corrections/modifications certified by the supervisor and must contain the following copyright certificate in the beginning of the thesis, on a separate page:

**©Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, New Delhi-110078. All rights reserved**

- 7.9.6 The University may issue a Provisional Certificate of the completion of M.Phil. to the research scholar upon M.Phil. notification, followed by award of the final degree at the time of convocation. The certificate and the degree shall mention the School, and the discipline in which the M.Phil. degree is awarded.

#### **8.0 Treatment of M.Phil. as full-time Registration**

- 8.1 M.Phil. Programmes shall not be offered through distance education mode.
- 8.2 Full-time M.Phil. shall be allowed for employed candidates when all the conditions mentioned in this Ordinance are met.

#### **9.0 Depository with INFLIBNET**

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the M.Phil. degree(s), the Examination Division shall provide an electronic copy of the M.Phil. Dissertation to the library of the University. The Librarian of the University Library shall ensure the submission of the said copy to the INFLIBNET.

- 10.0 The eligibility of the supervisors recognised by the University before the enactment of this ordinance shall be reviewed by the concerned SRC.

- 11.0** Operational guidelines for preparation of the admission brochure and its issuance shall be proposed by the RDC and implemented after approval of the Vice-Chancellor.
- 12.0** Operational guidelines for evaluation of the M.Phil. dissertation shall be proposed by the Controller of Examinations and implemented after approval of the Vice-Chancellor.
- 13.0** Notwithstanding anything stated in this Ordinance, if the Statutory Bodies regulating the M.Phil. programme, define any condition / specification at variance with this Ordinance, the same shall be applicable with the approval of the Vice-Chancellor, till necessary amendments are made in this Ordinance, incorporating the said new conditions / specifications. The concerned SRC shall propose the incorporation of the same.
- 14.0** Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion / advice of a Committee consisting of the RDC, and any or all the Deans of the Schools. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

This Ordinance shall come into force with effect from the date of approval of the Board of Management i.e. 25.06.2024.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar